दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

सुरक्षित: 10.04.2023

उद्घोषित: 30.05.2023

नि.प्र.अ. (मू.प.) 3/2019 एवं सि.वि. आ. 1031/2019

इंडिया स्किल्स प्राइवेट लिमिटेड
501, एम्पायर अपार्टमेंट,
98, एम.जी. रोड, सुल्तानपुर,
नई दिल्ली-110030 ..... अपीलार्थी

द्वारा: श्री ताहिर अशरफ सिद्दीकी, अधिवक्ता सह सुश्री स्वच्छा छेत्री, विधिक कार्यकारी।

बनाम

1 नीरज कुमार पाठक

पुत्र सत्य देव पाठक,
निवासी मकान सं. 65,
खानपुर गांव, चौपाल के पास,
खानपुर गांव, नई दिल्ली-62

2 मनोज कुमार

पुत्र स्वर्गीय भभूति,

निवासी मकान सं. 65,
गांव खानपुर,
नई दिल्ली ..... प्रत्यर्थीगण

द्वारा: श्री हेमंत मंजनी एवं सुश्री साक्षी गर्ग, अधिवक्तागण।

कोरम:
माननीय न्यायमूर्ति श्री सुरेश कुमार कैत
माननीय न्यायमूर्ति सुश्री नीना बंसल कृष्णा

निर्णय

न्या. नीना बंसल कृष्णा

1. वर्तमान अपील दिनांक 29.10.2018 के निर्णय के विरुद्ध दायर की गई है, जिसके माध्यम से प्रतिष्ठा की हानि के कारण 3 करोड़ रुपये की क्षति के लिए अपीलार्थी/वादी का वाद खारिज कर दिया गया है।

2. **संक्षिप्त तथ्य** यह हैं कि अपीलार्थी पिछले सात वर्षों से अभिनव मानव संसाधन मूल्यांकन समाधान प्रदान करने के व्यवसाय में लगी हुई एक कंपनी है और उसने भारत के सर्वश्रेष्ठ मानव संसाधन मूल्यांकन समाधान प्रदाता के रूप में काफी ख्याति और प्रतिष्ठा कमा ली है। इसका एक मजबूत ग्राहक आधार है जिसमें निम्नलिखित इकाइयां शामिल हैं:

क. *राष्ट्रीय कौशल विकास निगम;*

ख. *रिटेलर एसोसिएशन स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया;*

ग. *सुरक्षा क्षेत्र कौशल विकास परिषद;*

घ. *मोटर वाहन कौशल विकास परिषद;*

ङ. *खनन क्षेत्र के लिए कौशल परिषद;*

च. *वस्त्र कौशल विकास परिषद;*

छ. *रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय।*

3. प्रत्यर्थीगण शुरू में अपीलार्थी कंपनी के समन्वयक के रूप में लगे हुए थे। हालांकि, अपीलार्थी के अनुरोध पर, प्रत्यर्थी सं. 1 और 2 के साथ व्यक्तिगत रूप से दिनांक 12.03.2015 और 07.08.2015 के समझौता ज्ञापन (एमओयू) निष्पादित किए गए थे। प्रत्यर्थीगण मूल्यांकनकर्ताओं के प्रमाणन और अपीलार्थी द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार उचित मूल्यांकन प्रक्रिया पर उनके प्रशिक्षण के लिए जिम्मेदार थे। जबकि प्रत्यर्थी सं. 1 को राज्य के भीतर और साथ ही अपीलार्थी कंपनी द्वारा निर्देशित किए गए अनुसार राज्य के बाहर मूल्यांकन करने के लिए एक समन्वयक के रूप में नियुक्त किया गया था, वहीं प्रत्यर्थी सं. 2 को विशेष रूप से उत्तर प्रदेश राज्य के लिए समन्वयक के रूप में नियुक्त किया गया था।

4. समझौता ज्ञापन की प्रारंभिक अवधि एक वर्ष थी। प्रारंभ में प्रत्यर्थीगण ने अपीलार्थी कंपनी की संतुष्टि के लिए काम किया, लेकिन बाद में उनके काम की गुणवत्ता खराब हो गई। उनकी लापरवाही के बारे में फटकार लगाए जाने पर, प्रत्यर्थी सं. 1 ने अपीलार्थी कंपनी के प्रबंधक श्री जसजीत सिंह अहलूवालिया को दिनांक 08.07.2016, प्रदर्श अ.सा.-1/4 के ईमेल के माध्यम से एक पत्र लिखकर क्षमा मांगी।

5. एमओयू के खंड 2(थ) के अनुसार, यह सहमति हुई थी कि अपीलार्थी कंपनी द्वारा अपने प्रमुख ग्राहकों से भुगतान सूचना प्राप्त करने के 30 दिनों के भीतर प्रत्यर्थीगण को मूल्यांकन शुल्क का भुगतान किया जाएगा। यह प्रत्यर्थीगण का कर्तव्य था कि वे भुगतान के समय पर संग्रह और अपीलार्थी कंपनी के पक्ष में भुगतान जारी करने के लिए संबंधित अधिकारियों के साथ नियमित तौर पर भुगतान संबंधी अनुवर्ती कार्रवाई करें।

6. यह दावा किया गया था कि प्रतिवादीगण/प्रत्यर्थीगण ने अपीलार्थी कंपनी के लिए ईमानदारी से और पेशेवर रूप से काम करने के बजाय, न केवल अपने ग्राहकों बल्कि कर्मचारियों के बीच भी उनकी प्रतिष्ठा और सद्भावना को धूमिल करके बाजार में अपीलार्थी कंपनी को बदनाम करने

की घृणित और तुच्छ गतिविधियों का पालन करना शुरू कर दिया। प्रत्यर्थी सं. 1 ने अपीलार्थी कंपनी के विरुद्ध झूठे और निराधार आरोप लगाते हुए दिनांक 16.07.2016 को नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष को संबोधित एक ईमेल लिखा (प्रद. अभि.सा.1/5) और इसे अन्य सभी ग्राहकों को भी चिह्नित किया।

7. यह दावा किया गया था कि प्रत्यर्थी सं. 1 ने जानबूझकर विभिन्न निकायों को अपमानजनक ईमेल भेजे थे, जिसका एकमात्र उद्देश्य अपीलार्थी कंपनी की छवि को धूमिल करना और उन्हें बाजार में बदनाम करना था, जिससे अपीलार्थी के व्यवसाय, नाम और प्रतिष्ठा को काफी क्षति पहुंची है। उपरोक्त ईमेल से ऐसे प्रकथन सामने आए हैं जो पूरी तरह से अपमानजनक, एकदम दोषपूर्ण, पूरी तरह से अक्षम्य बदनामी थे और इससे अपीलार्थी कंपनी की प्रतिष्ठा, चरित्र और विश्वसनीयता को गंभीर, बेहिसाब और अपूरणीय क्षति पहुंची थी।

8. यह दावा किया गया था कि प्रत्यर्थी सं. 1 द्वारा भेजे गए इन दुर्भावनापूर्ण ईमेलों के कारण, कुछ ग्राहकों ने अपीलार्थी कंपनी को आगे और परियोजनाएं नहीं देने का निर्णय लिया। अपीलार्थी प्रत्यर्थी सं. 1 के विरुद्ध स्थायी और अनिवार्य व्यादेश के लिए वाद दायर करने के लिए

बाध्य था ताकि उसे कोई भी ईमेल भेजने से रोका जा सके, जिसमें इसके लिए अंतरिम व्यादेश दिया गया था। हालांकि, प्रत्यर्थी सं. 2 ने ईमेल भेजना जारी रखने के लिए प्रत्यर्थी सं. 1 के साथ हाथ मिलाया।

9. अपीलार्थी को 6,98,05,770/- रुपए की वित्तीय हानि और मानहानि हुई है और इस प्रकार उसने 3 करोड़ रुपए; प्रत्यर्थीगण से क्षमा और वाद की लागत की क्षतिपूर्ति के लिए भी वाद दायर किया है।

10. **प्रत्यर्थी सं. 1** समन आदि के बावजूद उपस्थित नहीं हुआ और लिखित बयान भी दर्ज नहीं किया और लिखित बयान दर्ज करने का उसका अधिकार समाप्त कर दिया गया और **दिनांक 03.03.2017 के आदेश के अंतर्गत उसकी एकपक्षीय कार्यवाही की गई।**

11. **प्रत्यर्थी सं. 2 उपस्थित हुआ** लेकिन लिखित बयान दर्ज नहीं किया और लिखित बयान दर्ज करने का उसका अधिकार भी दिनांक 29.05.2017 के आदेश के अंतर्गत समाप्त कर दिया गया।

12. इसके बाद, दोनों प्रत्यर्थीगण विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित हुए, जिन्होंने एकपक्षीय आदेश को अपास्त कराने के लिए आवेदन दायर करने के लिए समय मांगा, लेकिन लिखित बयान दर्ज करने के अधिकार को समाप्त करने के विरुद्ध एक चैंबर अपील प्रस्तुत की,

जिसे दिनांक 27.11.2017 के आदेश के अंतर्गत खारिज कर दिया गया था।

13. अपीलार्थी ने **अभि.सा.1** श्री विभास कुमार अपीलार्थी कंपनी के उपाध्यक्ष, **अभि.सा.2** श्री दिनेश वशिष्ठ अपीलार्थी कंपनी के पूर्व उपाध्यक्ष और **अभि.सा.3** श्री पवनजीत सिंह अहलूवालिया, अपीलार्थी कंपनी के निदेशक, का परीक्षण किया जिन्होंने अपने शपथपत्र क्रमशः प्रद. अभि.सा.1/क, प्रद. अभि.सा.2/क और प्रद. अभि.सा.3/क के माध्यम से अपने साक्ष्य प्रस्तुत किए।

14. *आक्षेपित निर्णय में विद्वान एकल न्यायाधीश* ने प्रत्यर्थी सं. 1 द्वारा अपीलार्थी के ग्राहकों को भेजे गए ईमेल दिनांक 16.07.2016, प्रदर्श अभि.सा.1/5 का संदर्भ दिया कि हालांकि शुरू में अपीलार्थी ने भुगतान किए थे, लेकिन उसके बाद भुगतान करने में उसकी गति धीमी होती चली गई और 15 लाख रुपये की राशि बकाया है और अपीलार्थी के अधिकारी इसे चुकाने के लिए सुविधा-शुल्क की मांग कर रहे हैं। 10.08.2016, प्रदर्श अ.सा.1/17 को प्रत्यर्थी सं. 1 की फेसबुक वॉल के फोटोशॉट का भी संदर्भ दिया गया था, जिसमें उसने बयान दिया था कि अपीलार्थी कंपनी एक धोखेबाज कंपनी है और गैर-पेशेवर है क्योंकि उसने अपने मूल्यांकनकर्ता

को भुगतान नहीं किए हैं और दूसरों को अपीलार्थी के साथ व्यवहार करने से सावधान किया था।

15. विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा अपीलार्थी के समक्ष एक विशिष्ट प्रश्न रखा गया था और यह देखा गया था कि अपीलार्थी, वादी/अपीलार्थी के नेतृत्व में इस आशय का कोई साक्ष्य दिखाने में सक्षम नहीं था कि उक्त तिथि पर प्रत्यर्थीगण द्वारा दावा की गई राशि अपीलार्थी की ओर से देय नहीं थी। वास्तव में, इस बात का ज़रा भी ज़िक्र नहीं हुआ कि प्रत्यर्थीगण द्वारा दिए गए बयान झूठे या मानहानिकारक थे। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकाला गया कि अपीलार्थी यह साबित करने में सक्षम नहीं है कि उसके विरुद्ध कोई मानहानिकारक बयान दिए गए थे और *मुकदमा खारिज कर दिया गया।*

16. उक्त निर्णय से व्यथित होकर, वर्तमान अपील प्रस्तुत की गई है।

17. **अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है** कि अपीलार्थी के मुख्य अधिवक्ता को दलीलों को संबोधित करने का पर्याप्त अवसर नहीं मिला और अपीलार्थी को निष्पक्ष सुनवाई का मौका दिए बिना आक्षेपित निर्णय दिया गया है। यह प्रस्तुत किया गया है कि साक्षियों ने अपने साक्ष्य में स्पष्ट रूप से यह कहने के बावजूद कि प्रत्यर्थीगण द्वारा दिए

गए बयान मानहानिकारक और झूठे थे, विद्वान एकल न्यायाधीश गलती से इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि वादी/अपीलार्थी यहां यह दर्शाने में विफल रहे कि प्रत्यर्थीगण द्वारा दिए गए बयान मानहानिकारक या झूठे थे।

18. आगे यह तर्क दिया गया है कि अपीलार्थी के दस्तावेजी साक्ष्य पर विचार नहीं किया गया है कि अपीलार्थी से प्रत्यर्थीगण पर कोई देय नहीं था। एमओयू के खंड 2 (थ) और 2 (द), प्रद. अभि.सा.1/2 में शर्तों का उल्लेख करके यह तर्क दिया गया था कि अपीलार्थी के खाते में ग्राहकों द्वारा राशि जमा किए जाने के बाद ही प्रत्यर्थीगण को धन का भुगतान किया जाना था। यह प्रत्यर्थी पर निर्भर था कि वह अनुबंध के संदर्भ में धन प्राप्त करने के लिए ग्राहकों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई करे। यह वे हैं जो अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में विफल रहे और उन्होंने अपीलार्थी को गलत तरीके से आलिप्त किया है। आगे यह तर्क दिया गया है कि वास्तव में, प्रत्यर्थीगण का कोई परादेय दावा नहीं था और यही कारण है कि उन्होंने आज तक अपीलार्थी के विरुद्ध वसूली के लिए कोई वाद दायर नहीं किया है।

19. इसके अतिरिक्त, दिनांक 16.07.16 का मानहानिकारक ईमेल, प्रद. अभि.सा.1/5, जो प्रत्यर्थी सं.1 द्वारा अपने विभिन्न ग्राहकों को भेजा गया

था, जिसके परिणामस्वरूप अपीलार्थी को व्यवसाय की हानि हुई और उसके विभिन्न ग्राहकों द्वारा संबद्धता समाप्त कर दी गई। वास्तव में, प्रत्यर्थी आरंभ में सतर्क थे, परंतु वे लापरवाही करने लगे और लापरवाह हो गए और उनकी कार्य गुणवत्ता का क्षय हुआ और जब उन्हें इसके लिए फटकार लगाई गई तो प्रत्यर्थी सं.1 ने अपीलार्थी कंपनी से क्षमा भी मांगी।

20. इसके अतिरिक्त, प्रत्यर्थीगण के पास कोई बचाव नहीं था, जिस कारण से न तो उन्होंने कोई लिखित बयान दर्ज किया और न ही उन्होंने साक्षियों का प्रतिपरीक्षण किया। अपीलार्थी के वाद को दोषपूर्ण ढंग से खारिज कर दिया गया है जबकि इसे वाद-पत्र की प्रार्थना के अनुसार अधिनिर्णीत किया जाना चाहिए था।

21. **प्रत्यर्थीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है** कि चूंकि अपीलार्थी को किए गए दावे बकाया थे, इसलिए कोई मानहानिकारक बयान नहीं दिया गया था, और उसने केवल आक्षेपित ईमेलों के माध्यम से देय राशि की मांग की थी। प्रत्यर्थीगण द्वारा कोई झूठा बयान नहीं दिया गया था और इसलिए, कोई मानहानिकारक मामला नहीं सिद्ध किया गया था। वाद खारिज कर दिया गया है।

22. **प्रस्तुतियां सुनी गईं।**

23. अपीलार्थी का मामला यह है कि कथित मानहानिकारक ईमेल दिनांक 16.07.2016 को, प्रद. अभि.सा.1/5 जो प्रत्यर्थी सं.1 और प्रत्यर्थी सं.2 द्वारा भारत के राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के अध्यक्ष को सीसी के साथ सभी ग्राहकों और उनकी फेसबुक वॉल पर पोस्ट के साथ लिखे गए थे, जिसके परिणामस्वरूप उनकी मानहानि, प्रतिष्ठा की हानि और कई ग्राहकों के व्यावसायिक खाते की हानि हुई है।

24. अपीलार्थी की दलीलों को समझने के लिए, सबसे पहले "मानहानि" और "प्रतिष्ठा" की अवधारणा को समझना महत्वपूर्ण होगा।

<u>"मानहानि" शब्द का अर्थ</u>

25. **चैम्बर्स ट्वेंटीथ सेंचुरी डिक्शनरी**, के अनुसार मानहानि का अर्थ है अच्छी प्रसिद्धि या प्रतिष्ठा को छीनना या नष्ट करना; बुरा बोलना या; झूठा आरोप लगाना या निंदा करना।

26. **सैल्मंड और हेस्टन** ऑन द लॉ ऑफ टॉर्ट्स के, 20वां संस्करण 7 में एक मानहानिकारक कथन को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है: -

> *"एक मानहानिकारक बयान वह है जिसमें उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाने की प्रवृत्ति होती है जिसे वह संदर्भित करता है; जो, कहने का तात्पर्य यह है कि, आम तौर पर और विशेष रूप से समाज के सही सोच वाले सदस्यों के आकलन में उसे नीचा*

दिखाने के लिए उसे घृणा, अवमानना, उपहास, भय, नापसंदगी या असम्मान की भावना से देखा जाता है। बयान को समाज के किसी भी साधारण, सही सोच वाले सदस्य के मानक से आंका जाता है ..."

27. **हाल्सबरीस लॉस ऑफ इंग्लैंड**, का चौथा संस्करण, वॉल्यूम 28, एक "मानहानिकारक बयान" को निम्नानुसार परिभाषित करता है: -

"अपमानजनक बयान एक ऐसा बयान है जो किसी व्यक्ति को आम तौर पर समाज के सही सोच वाले सदस्यों की नजर में गिरा देता है या उसे तिरस्कृत कर देता है या टाल देता है या उसे घृणा, अवमानना या उपहास का पात्र बना देता है, या उसके कार्यालय, पेशे, कॉलिंग ट्रेड या व्यवसाय में उसके लिए अपमानजनक या हानिकारक लांछन लगाता है।"

28. *स्कॉट बनाम सैम्पसन* क्यूबीडी1882 के मामले में **न्यायमूर्ति केव** ने इसे "किसी व्यक्ति को बदनाम करने के लिए उसके बारे में दिए गलत बयान" के रूप में परिभाषित किया। इसे *बाटा इंडिया लिमिटेड बनाम ए.एम. तुराज़ और अन्य* 2013 (53) पीटीसी 586; *पांडे सुरिन्द्र नाथ सिन्हा बनाम बागेश्वरी पीडी.* एआईआर 1961 पैट. 164 (1882) क्यूबीडी 491 के निर्णयों में भी लागू किया गया था।

<u>"प्रतिष्ठा" की अवधारणा</u>

29. "मानहानि" से निपटने के बाद, "प्रतिष्ठा" के आंतरिक पहलुओं और प्रतिष्ठा का गठन करने पर विचार किया जा सकता है। *<u>मनीषा कोइराला बनाम शशि लाल नायर एवं अन्य</u>*, 2003 (2) बॉम्बे सीआर 136, में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि संकेत स्पष्ट रूप से "प्रतिष्ठा" के सहज सार्वभौमिक मूल्य को उजागर करेंगे और यह जीवन का एक पोषित घटक है और समय से सीमित या प्रतिबंधित नहीं है। विवरण अलग हो सकता है, लेकिन महत्वपूर्ण आधार समान है।

30. **विलियम हज़लिट** ने प्रतिष्ठा की अवधारणा को इस प्रकार समझाया है:-

> *"एक आदमी की प्रतिष्ठा अपने स्वयं के हाथ में नहीं, बल्कि दूसरों की दया पर निहित होती है। बदनामी को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। किसी भी चरित्र के विरुद्ध दुर्भावनापूर्ण लांछन लगाने से एक ऐसा दाग लग जाता है, जिसे बाद में किया गया कोई भी खंडन मिटा नहीं सकता। प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि कुछ बातें सत्य हों, बल्कि केवल यह आवश्यक है कि वे कही गई हों। कल्पना की बनावट इतनी*

नाजुक होती है कि शब्द भी उस पर घाव कर देते हैं"।

31. **लॉर्ड डेनिंग** ने *प्लेटो फिल्म्स लिमिटेड बनाम स्पीडेल* (1961) 1 ऑल ई.आर. 876 में चरित्र और प्रतिष्ठा के बीच के अंतर को संक्षेप में निम्नानुसार समझाया है:

"कभी-कभी यह कहा जाता है कि किसी व्यक्ति का "चरित्र" वैसा ही होता है जैसा वह है, जबकि उसकी "प्रतिष्ठा" वही होती है जो दूसरे लोग उसके बारे में सोचते हैं। यदि यह वह अर्थ है जिसमें आप शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, तो मानहानि की कार्रवाई का संबंध केवल एक व्यक्ति की प्रतिष्ठा से है, अर्थात लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं: और यह उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए है, अर्थात, दूसरों की नजर में उसके सम्मान के लिए, कि वह मुकदमा कर सकता है, न कि उसके अपने व्यक्तित्व या स्वभाव को नुकसान पहुंचाने के लिए"।

32. *ओम प्रकाश चौटाला बनाम कंवर भान व अन्य* (2014) 5 एससीसी 417 मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि प्रतिष्ठा मूल रूप से गुणों का एक शानदार मिश्रण और एकीकरण है जो एक व्यक्ति को अपने वंश पर गर्व महसूस कराता है और उसे भावी पीढ़ी

के लिए विरासत के एक हिस्से के रूप में विरासत में देने के लिए संतुष्ट करता है। यह अपने आप में एक बड़प्पन है जिसके लिए एक कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति कभी भी चीन की सारी चाय या समुद्र के सभी मोतियों के साथ इसका आदान-प्रदान नहीं करेगा। जब प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है तो आदमी अधमरा हो जाता है। यह एक सम्मान है जिसे वंचितों और विशेषाधिकार प्राप्त लोगों द्वारा समान रूप से संरक्षित किया जाना चाहिए। कोई भी यह नहीं चाहेगा कि उसकी प्रतिष्ठा पर बट्टा लगे और इसे लोकप्रियता के बजाय सम्मान के रूप में देखा जाता है।

33. *विश्वनाथ अग्रवाल बनाम सरल विश्वनाथ अग्रवाल* (2012) 7 एससीसी 288 के मामले में शीर्ष न्यायालय ने कहा कि प्रतिष्ठा न केवल जीवन की संपदा है, बल्कि जीवन का सबसे अच्छा खजाना और सबसे कीमती सुगंध भी है। यह वर्तमान के साथ-साथ भावी पीढ़ी के लिए भी राजस्व सृजक है।

34. *उमेश कुमार बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य* (2013) 10 एससीसी 591 मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अच्छी प्रतिष्ठा व्यक्तिगत सुरक्षा का एक तत्व है और संविधान द्वारा इसे जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के आनंद के अधिकार के साथ समान रूप से

संरक्षित किया गया है और इस तरह इसे संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक नागरिक के जीवन के अधिकार के संबंध में एक आवश्यक तत्व माना गया है।

35. *जेफरी जे. डिएर्मियर और अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य* (2010) 6 एससीसी 243 में, इस पहलू पर विचार करते हुए कि भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 499 के अंतर्गत मानहानि क्या है, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि कोई लांछन होना ही चाहिए और ऐसा लांछन नुकसान पहुंचाने के इरादे से लगाया गया होगा या यह जानने या विश्वास करने का कारण होगा कि इससे उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचेगा जिसके बारे में यह लगाया गया है।

36. **कार्टर-रक ऑन लिबेल एंड स्लैंडर, के पांचवें संस्करण में** कुछ परीक्षणों को निम्नानुसार उकेरा गया है: -

> *"(1) किसी भी व्यक्ति से संबंधित एक बयान जो उसे घृणा, उपहास, या अवमानना के लिए उजागर करता है, या जिसके कारण उसे त्याग दिया जाता है या टाला जाता है, या जो उसे अपने कार्यालय, पेशेवर या व्यापार में चोट पहुंचाने की प्रवृति रखता है।*

(2) किसी व्यक्ति के बारे में उसकी बदनामी के लिए गलत बयान देना।

(3) क्या ये शब्द आम तौर पर समाज के सही सोच वाले सदस्यों के आकलन में वादी को कमतर करेंगे?"

<u>मानहानि:</u>

37. संक्षेप में, मानहानि का अपराध किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को होने वाली क्षति है। यह दिखाने के लिए पर्याप्त होगा कि अभियुक्त का इरादा था या वह जानता था या उसके पास यह विश्वास करने का कारण था कि उसके द्वारा लगाए गए आरोप से शिकायतकर्ता की प्रतिष्ठा को नुकसान होगा, भले ही शिकायतकर्ता को वास्तव में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कथित आरोप से नुकसान हुआ हो। संक्षेप में, कोई भी बयान जिसमें व्यक्ति की प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाने या समाज के सदस्यों के अनुमान में उसे कम करने की प्रवृत्ति हो, मानहानिकारक है और इसके परिणामस्वरूप प्रतिष्ठा की हानि होती है।

38. <u>*राम जेठमलानी बनाम सुब्रमण्यम स्वामी*</u>, 126 (2006) डीएलटी 535 में मानहानि को सार्वजनिक संचार के रूप में परिभाषित करते हुए, जो दूसरे की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाता है, न्यायालय ने *मानहानि के*

वाद में उपलब्ध सत्य, निष्पक्ष टिप्पणी और विशेषाधिकार के बचाव की व्याख्या की। यह निम्नानुसार है:

> "*मानहानि की कार्रवाई के लिए **पारंपरिक बचाव** अब काफी ठोस हो गए हैं और **इन्हें तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है: सत्य, निष्पक्ष टिप्पणी और विशेषाधिकार।** सत्य, या औचित्य, पूर्ण बचाव है। सत्य के प्रमाण का मानक पूर्ण नहीं है बल्कि यह स्थापित करने तक ही सीमित है कि जो कहा गया वह 'काफी हद तक सही था। निष्पक्ष टिप्पणी विचारों की अभिव्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करती है। सबूत का मानक यह नहीं है कि न्यायालय को राय से सहमत होना है, बल्कि यह निर्धारित करने तक सीमित है कि क्या विचार उस समय ज्ञात तथ्यों पर निष्पक्ष सोच वाले व्यक्ति द्वारा ईमानदारी से रखे जा सकते थे। सत्य की रक्षा के विपरीत, निष्पक्ष टिप्पणी पर आधारित रक्षा विफल हो सकती है यदि वादी यह साबित कर दे कि मानहानि करने वाले ने दुर्भावना से काम किया है। ऐसी ही स्थिति है जहां बचाव योग्य विशेषाधिकार का है। विशेषाधिकार को जनता की भलाई के लिए की गई अभिव्यक्ति की सुरक्षा के लिए रचा गया है। यदि वास्तविक द्वेष स्थापित हो जाता है तो योग्य विशेषाधिकार की सुरक्षा समाप्त हो जाती है। सार्वजनिक हित में, पूर्ण विशेषाधिकार पूर्ण रक्षा है।*

संपूर्ण विशेषाधिकार को न्यायालय कार्यवाही या अधिकरण के समक्ष कार्यवाही तक सीमित रखने का तर्क, जिसमें सिविल न्यायालय और संसदीय कार्यवाही के सभी गुण हैं, यह है कि यदि वकीलों, वादकारियों, साक्षियों, न्यायाधीशों और सांसदों के सिर पर मानहानि के मुकदमे का खतरा मंडराता है तो यह उन्हें स्वतंत्र रूप से बोलने से रोक देगा और सार्वजनिक हित को नुकसान होगा।'

वर्तमान मामले में, इस बात का परीक्षण करने की आवश्यकता है कि क्या प्रत्यर्थीगण ने अपीलार्थी और उसके ग्राहकों के साथ ईमेल के आदान-प्रदान में अपने दावों को आगे बढ़ाने के अपने अधिकार का उल्लंघन किया है। पहला ईमेल जिसके बारे में दावा किया गया है कि वह मानहानिकारक है और सभी ग्राहकों को संबोधित है, दिनांक 16.07.2016 प्रद..अभि.सा.1/5 का है जो इस प्रकार है:

"सभी आदरणीय विधिक प्राधिकारीगण,
मैं नीरज पाठक मकान नंबर-65, खानपुर गांव, नई दिल्ली-110062, इंडिया स्किल्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में राज्य समन्वयक के पद पर कार्यरत हूं, वर्तमान पता सूट #501, द एम्पायर अपार्टमेंट, 98 एमजी रोड, सुल्तानपुर, नई दिल्ली-110032 है।

मैं मार्च 2014 में इंडिया स्किल्स प्राइवेट लिमिटेड में मूल्यांकन राज्य समन्वयक के रूप में शामिल हुआ हूं। मैंने 2014 से आज तक इंडिया स्किल्स प्राइवेट लिमिटेड के लिए लगभग 2 करोड़ का बिजनेस किया है। आप व्यवसाय के ट्रैकर की जांच कर सकते हैं।

मैं राज्य समन्वयक के रूप में इंडिया स्किल्स प्राइवेट लिमिटेड के लिए मूल्यांकनकर्ता के रूप में योग्य कार्यबल प्रदान करता हूं। नवंबर 2015 तक इंडिया स्किल्स कंपनी नियमित आधार पर भुगतान प्रदान कर रही थी। लेकिन उसके बाद कंपनी मुझे बहुत धीरे-धीरे रकम का भुगतान करती है। मेरी 15 लाख से अधित की बकाया राशि अभी भी लंबित है। जब मैंने अपने भुगतान के लिए कंपनी के लेखा प्रबंधक श्री ज्योति रंजन और व्यवसाय विकास प्रबंधक श्री गौरव कुमार से बात की तो उन्होंने मुझसे सुविधा शुल्क के रूप में कुछ % मांगा। जब मैंने उन्हें किसी भी प्रकार का % देने से इंकार कर दिया तो वे अब मुझे नजरअंदाज कर रहे हैं। जब मैंने सारा मामला कंपनी के सीएमडी को बताया तो वह भी मेरी समस्या नहीं सुन रहे हैं। उन्होंने एक वीपी नियुक्त किया, जिसका नाम दिनेश बासिस्ट मोबाइल नंबर 9871008025 है। जब मैंने कंपनी वीपी से बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने मुझसे कहा कि जब भुगतान आएगा तब हम आपको

प्रदान करेंगे। महोदय, जब मैंने उनसे पूछा कि कृपया मुझे अपना भुगतान ट्रैकर दिखाएं तो वह भी सकारात्मक जवाब नहीं दे रहे हैं।

महोदय, संलग्न ट्रैकर के अनुसार मैंने सरकारी परियोजनाओं के लिए इंडिया स्किल्स अर्थात सेक्टर स्किल्स काउंसिल को मूल्यांकनकर्ता उपलब्ध कराए हैं, जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना द्वारा प्रबंधित होते हैं। मैंने सुरक्षा क्षेत्र कौशल परिषद, खुदरा क्षेत्र कौशल परिषद, कपड़ा, ऑटोमोबाइल, दूरसंचार, उत्तर प्रदेश कौशल विकास योजना और अन्य परियोजनाओं डीडीयूजीकेवाई, यूपी एसयूडीए, एनयूएलएम, डीजीईटी आदि के लिए काम किया है।

अब कुछ दिनों पहले कुछ मूल्यांकनकर्ताओं ने मुझ पर दबाव बनाया तो मैंने सीएमडी श्री जसजीत आहुवालिया मो.सं. 9650470000 को बताया (प्रीमियर शील्ड प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक पवनजीत सिंह आहुवालिया के पुत्र मोबाइल नंबर 9958694200), और उन्होंने भुगतान करने से इनकार कर दिया और मुझे चेतावनी भी दी कि श्री नीरज आप मुझे नहीं जानते, मेरे पास आपके जैसे 10 हजार लोग हैं। महोदय, अब मेरी स्थिति करो या मरो वाली हो गई है।

महोदय, अत्यंत विनम्रतापूर्वक और सम्मानपूर्वक मैं कहना चाहता हूं कि मुझे हमारे मूल्यांकनकर्ताओं को भुगतान करना है लेकिन इंडिया स्किल्स प्राइवेट लिमिटेड मुझे मेरा भुगतान नहीं दे रही है और न ही वह मुझे अपना भुगतान ट्रैकर दिखाने के लिए तैयार है।
कंपनी के सीएमडी मुझे चेतावनी दे रहे हैं।

इसलिए मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि कृपया इस मामले को अपनी ओर से देखें और मुझे जल्द से जल्द समाधान प्रदान करें।
आपकी सकारात्मक प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा रहेगी।
आदर सहित धन्यवाद
नीरज कुमार पाठक
9555552356"

40. प्रत्यर्थीगण ने प्राख्यान दिया है कि जैसा कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने देखा था, अपीलार्थी से 15 लाख रुपये की बकाया राशि का दावा किया गया था।

41. इसके अतिरिक्त, अपीलार्थी ने 10.08.2016 को प्रत्यर्थी सं. 1 और पवनजीत सिंह अहलूवालिया, अभि.सा.-3 के बीच आदान-प्रदान किए गए

पाठ संदेशों पर भरोसा किया है, जिन्हें साक्ष्य के शपथपत्र में निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया है:

> "***प्रत्यर्थी सं. 1:***
> *प्रिय महोदय,*
> *अब मैं इंडिया स्किल्स टीम की धोखाधड़ी के बारे में एनएसडीसी शिकायत सेल और एसएससी को दोबारा मेल भेज रहा हूं। कृपया यह न पूछें कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं क्योंकि हमें आपकी टीम से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। इसके लिए बहुत खेद है।*
> *सादर अभिवादन*
> *नीरज पाठक*
>
> ***सीएमडी का उत्तर :***
> *क्या आप मुझे धमकी दे रहे हैं?*
>
> ***प्रत्यर्थी सं. 1:***
> *पिछले 6 महीनों से आपकी इंडिया स्किल्स टीम मुझे बेवकूफ बना रही है इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या करना है???*
> *मेरे पास कोई विकल्प नहीं बचा है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या करना है? मैं भीख नहीं मांग रहा हूं महोदय..... मैं अपने पैसे की मांग कर रहा हूं इसलिए मैं वे सभी चीजें करूंगा जो मेरे और इंडिया स्किल्स के लिए भी बुरी हैं।*

सीएमडी :

मैं दिल्ली से बाहर हूं। अगले हफ्ते मंगलवार को ओखला में मुझसे मिलो। हम 16 को सुबह मिलने का समय तय कर सकते हैं।

प्रत्यर्थी सं. 1:

महोदय, मुझे आज ही विभास के वादे के अनुसार तत्काल 5 लाख रुपये चाहिए क्योंकि मैंने भी आगे वचन दे दिया है। उसके बाद मैं आपसे मिलूंगा। आप इंडिया स्किल्स टीम से पूछ सकते हैं। मेरी बकाया राशि लगभग 12-13 लाख रुपये है।

सीएमडी :

मैं यात्रा कर रहा हूं और अगले सप्ताह मंगलवार के बाद ही आपकी कोई मदद कर सकता हूं।

प्रत्यर्थी सं. 1:

कोई बात नहीं महोदय, आप यात्रा कर रहे हैं, मैं समझ सकता हूं लेकिन लेखा विभाग तो यात्रा नहीं कर रहा है। मैं देख रहा हूं कि आप बड़े लोग हैं इसलिए आप इस तरह की बात कर रहे हैं। कोई बात नहीं मैं समझ रहा हूं कि वास्तव में आप भुगतान करना ही नहीं चाहते हैं। आपका इरादा स्पष्ट रूप से दिख रहा है। इंडिया स्किल्स प्राइवेट

लिमिटेड एक धोखेबाज कंपनी है..... वे अपने सहयोगियों के साथ काम करने और व्यवहार करने के अपने तरीके से वास्तव में और पेशेवर रूप से यही दिखाते है। वे अपने मूल्यांकनकर्ता के भुगतान का भुगतान भी नहीं करते हैं, इसलिए मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करता हूं कि उनके साथ काम करने से पहले बस जांच-परख कर लें। वहां का प्रबंधन हमेशा झूठी प्रतिबद्धताएं करता है... तो कृपया इंडिया स्किल्स प्राइवेट लिमिटेड से सावधान रहें।

कृपया इसे अधिक से अधिक साझा करें।

मैं अब यह संदेश फैला रहा हूं।

क्षमा करें, महोदय"।

42. इस ईमेल में भी बकाया राशि की मांग की गई है।

43. अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी सं. 1 की फेसबुक वॉल के दिनांक 10.08.2016 प्रद.अभि.सा.1/17 और 16.08.16 को प्रद.अभि.सा.1/18 के फोटोशॉट पर भी भरोसा किया है। यह निम्नानुसार है:

"नीरज पाठक,

10 अगस्त दोपहर 2:19 बजे, नई दिल्ली।

इंडिया स्किल्स प्राइवेट लिमिटेड एक धोखेबाज कंपनी है..... वे अपने सहयोगियों के साथ काम करने और व्यवहार करने के अपने तरीके से वास्तव में और

पेशेवर रूप से यही दिखाते है। वे अपने मूल्यांकनकर्ता के भुगतान का भुगतान भी नहीं करते हैं, इसलिए मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करता हूं कि उनके साथ काम करने से पहले बस जांच-परख कर लें। वहां का प्रबंधन हमेशा झूठी प्रतिबद्धताएं करता है... तो कृपया इंडिया स्किल्स प्राइवेट लिमिटेड से सावधान रहें।

नीरज पाठक,
अगस्त 16 पर 10:45 बजे

इंडिया स्किल्स प्राइवेट लिमिटेड की शिकायत प्रति... यह एक मूल्यांकन एजेंसी है जो डी.जी.ई.टी. और एन.एस.डी.सी. के लिए काम करती है... इस कंपनी का प्रबंधन बहुत खराब है और धोखेबाजी भी कर रहा है। इस कंपनी ने मेरे जैसे 20 से अधिक लोगों के साथ भी धोखाधड़ी की है। इस कंपनी से सावधान रहें... मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि कृपया इस संदेश को अधिक से अधिक साझा करें ताकि भारत सरकार इस कंपनी का पंजीकरण रद्द कर सके और इस कंपनी और कंपनी के निदेशकों को तुरंत ब्लैकलिस्ट कर सके... दोस्तों, कंपनी निदेशक और प्रबंधन ने मेरे पैसे नहीं दिए और धमकी भी दे रहे हैं... इसलिए मैं यह शिकायत पत्र सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहा हूं। कृपया मेरा सहयोग करें"।

44. प्रत्यर्थी सं. 1 और अभि.सा.-3, पवनजीत सिंह अहलूवालिया, इंडिया स्किल्स लिमिटेड के निदेशक के बीच आदान-प्रदान किए गए बाद के पाठ संदेशों के आलोक में, दिनांक 16.07.2016, प्रद. अभि.सा.1/5 के ईमेल को व्यापक रूप से पढ़ने से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी कंपनी पर बकाया राशि बकाया थी जिसके लिए प्रत्यर्थीगण वाद-विवाद कर रहे थे। विद्वान एकल न्यायाधीश ने ठीक ही कहा है कि दलीलों या साक्ष्यों में कहीं भी अपीलार्थी या उसके साक्षियों ने यह नहीं कहा कि राशि देय नहीं थी। प्रत्यर्थी का यह प्राख्यान कि राशि बकाया है जिसका भुगतान अपीलार्थी कंपनी द्वारा नहीं किया गया था, को गलत या मानहानिकारक नहीं कहा जा सकता है। जैसा कि *राम जेठमलानी* (पूर्वोक्त) के मामले में देखा गया, सच्चाई और निष्पक्ष टिप्पणी मानहानि का पारंपरिक बचाव है।

45. अपीलार्थी ने यह प्राख्यान देने के लिए एमओयू के खंड 2 (थ) और 2 (द) का सहारा लेने की कोशिश की है कि अपीलार्थी के पक्ष में धन जारी करने के लिए ग्राहकों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई करने की जिम्मेदारी प्रत्यर्थीगण की थी, ताकि प्रत्यर्थीगण को भुगतान किया जा सकता है। ऐसी समझ हो सकती है कि प्रत्यर्थीगण को भी ग्राहकों के साथ अनुवर्ती

कार्रवाई करनी होगी, लेकिन इससे बकाया राशि का भुगतान करने का अपीलार्थी का दायित्व समाप्त नहीं होता है। विद्वान एकल न्यायाधीश के निष्कर्षों से व्यथित होने के बावजूद, अपीलार्थी एक बार फिर अपनी दलीलों या अपने साक्ष्य से यह दिखाने में सक्षम नहीं हुआ कि अपीलार्थी की ओर से प्रत्यर्थीगण का कोई बकाया नहीं था।

46. यह भी देखा जा सकता है कि अपीलार्थी ने अपने प्राख्यानों के अनुसार केवल प्रत्यर्थी सं.1 के विरुद्ध स्थायी व्यादेश के लिए वाद दायर किया था। प्रत्यर्थी सं. 2 के विरुद्ध एकमात्र प्रकथन यह है कि उसने प्रत्यर्थी सं. 1 के साथ हाथ मिलाया, लेकिन प्रत्यर्थी सं. 2 द्वारा मानहानि के किसी भी कृत्य या प्रत्यर्थी सं. 1 के साथ उसकी मिलीभगत के रूप में व्याखया करने में विफल रहा।

47. यह तर्क दिया गया है कि न तो प्रत्यर्थीगण ने लिखित बयान दाखिल किया था और न ही साक्षियों से प्रतिपरीक्षा की थी और इस प्रकार यह साबित करने की जिम्मेदारी कि कोई बकाया राशि थी, जिसका भुगतान नहीं किया गया है प्रत्यर्थीगण पर थी। हालांकि, मामले को साबित करने का भार शुरू में अपीलार्थी पर था और केवल अगर वह इस तरह के शुरुआती बोझ का निर्वहन करने में सक्षम होता, तो जिम्मेदारी

प्रत्यर्थीगण पर आ जाती। ऊपर दिए गए ईमेलों से, अपीलार्थी द्वारा इस बात से इनकार नहीं किया गया है कि दावा की गई राशि देय नहीं थी और इस प्रकार, यह नहीं कहा जा सकता है कि प्रत्यर्थीगण के दावे या ईमेल में प्रत्यर्थीगण द्वारा किए गए दावे झूठे थे।

48. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हमें वर्तमान अपील में कोई गुणागुण नहीं मिलता है, जिसे एतद्द्वारा खारिज किया जाता है।

(नीना बंसल कृष्णा)
न्यायाधीश

(सुरेश कुमार कैत)
न्यायाधीश

30 मई 2023
वीए

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्द्मेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।